भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 522
दिनांक 06 फरवरी, 2024 / 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

केरल में माओवादी पोस्टर

†522. श्री वी.के. श्रीकंदनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केरल राज्य में कुछ स्थानों पर माओवादी पोस्टर दिखाई दिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि हाल ही में केरल में पुलिस मुठभेड़ में एक महिला माओवादी नेता की मौत हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश के अन्य भागों से माओवादी केरल जा रहे हैं और केरल में हुई घटनाएं आंखें खोलने वाली हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख) : वर्ष 2023 में सीपीआई/माओवादी के नाम पर कथित रूप से जारी पोस्टर कन्नूर तथा वायनाड जिलों से बरामद हुए थे। पोस्टरों में दावा किया गया था कि 13 नवंबर, 2023 को कन्नूर जिले में सुरक्षा बलों के साथ एक्सचेंज ऑफ़ फायर में एक महिला सीपीआई/माओवादी कैडर की मौत हो गई थी। हालांकि, राज्य पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है ।

(ग): केरल में निकटवर्ती राज्यो के सीपीआई/माओवादी कैडर सक्रिय हैं।

(घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों से संबंधित हैं। तथापि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता करती रहती है। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने संबंधी एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना" को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस नीति में एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.522, दिनांक 06.02.2024

जहां सुरक्षा की दृष्टि से, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनों, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियों, उपकरण एवं हथियारों, आसूचना के आदान-प्रदान, किलेबंद पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि का प्रावधान करके एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्य सरकार की सहायता करती है, वहीं विकास की दृष्टि से, फ्लैगशिप स्कीमों के अलावा, भारत सरकार ने सड़क नेटवर्क में विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, कौशल निर्माण और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देते हुए एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में अनेक विशिष्ट पहलें की हैं।

जहां तक केरल राज्य का संबंध है, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत विशेष बलों, विशेष खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत करने के लिए धनराशि प्रदान की गई है। इसके अलावा, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत संचालन, शिविर के बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण आदि पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए धन जारी किया जा रहा है।

*****